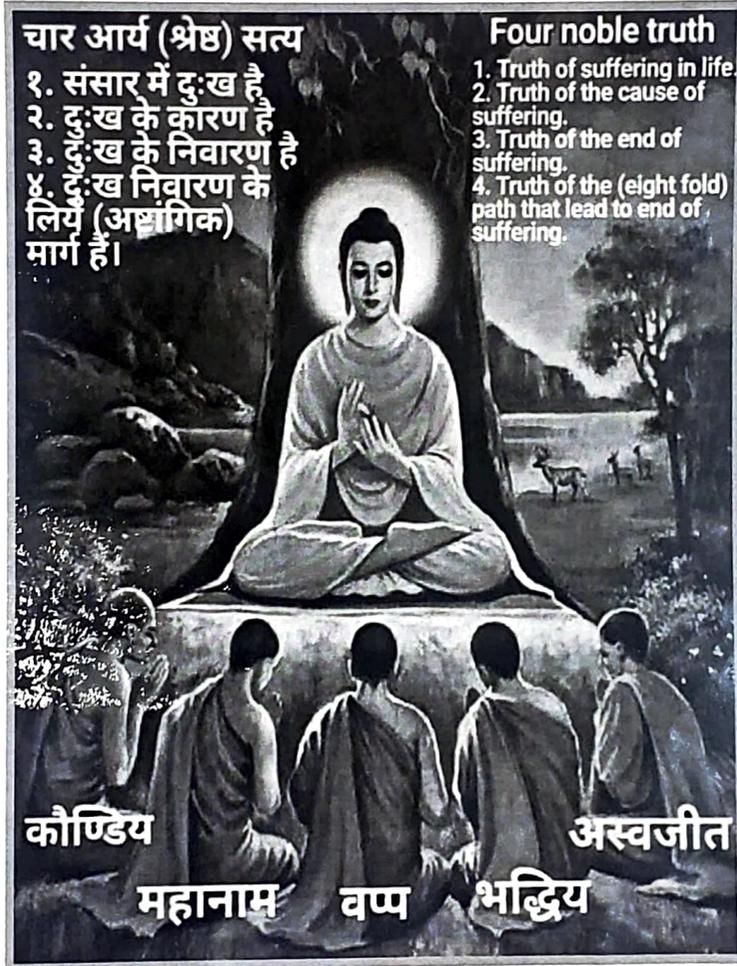


आश्वस्त

वर्ष 24, अंक 225

जुलाई 2022

आषाढ पौर्णिमा और प्रथम धम्मचक्र
प्रवर्तन दिन की सभी को मंगलकामनाएं।



संपादक - डॉ. तारा परमार



संस्थापक सम्पादक
डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक
सेवाराम खाण्डेगर
11/3, अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श
आयु. सूरज डामोर IAS
पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक
डॉ. तारा परमार
9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :
डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली
डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात
डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात
डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

Peer Review Committee

डॉ. श्रवणकुमार मेघ, जोधपुर(राजस्थान)
प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर, मुंबई (महाराष्ट्र)
प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, उज्जैन (म.प्र.)
डॉ. बी.ए.सावंत, सांगली (महाराष्ट्र)

कानूनी सलाहकार
श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र. विषय	लेखक	पृष्ठ
1. अपनी बात	डॉ. तारा परमार	03
2. सांख्ये सृष्टि युत्पति:	मोहनलाल	04
3. अमृतनादोपनिषद् में प्रणव उपासना	विवेक कुमार	06
4. गुरु नानक वाणी में वर्ण व जाति व्यवस्था का संदर्भ	उज्जवल अरुण मस्के	10
5. समावेशी शिक्षा का विकास एवं ऐतिहासिक परिदृश्य	डॉ. रवीन्द्र गासो	12
7. आदिवासी भाषा-संस्कृति और समाज का बदलेंगे स्वरूप	डॉ. खीमाराम काक	19
8. उत्तराखण्ड के खाड़ी प्रवासियों पर आश्रित महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति	डॉ. रविशरण दीक्षित	24
9. लघुकथा	सहायक आचार्य बी.एल. परमार	26

UGC Care Listed Journal

खाते का नाम - आश्वस्त (Ashwast)

खाते का नं.- 63040357829

बैंक - भारतीय स्टेट बैंक,

शाखा- फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)

IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com

E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	:	रुपये 20/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 200/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	:	रुपये 2,000/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 20,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेंगा।

आदिवासी भाषा—संस्कृति और समाज का बदलेगें स्वरूप

— ओमप्रकाश सैनी

प्रस्तावना : भारतीय ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में विमर्श की दृष्टि से हाशिए के समाजों विशेषकर दलित, स्त्री, वृद्ध, किन्नर, आदिवासी आदि को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है जो उत्तर आधुनिकता की देन है। भारतीय साहित्य में दलित एवं स्त्री विमर्श को लेकर सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वहीं आदिवासी समाज अपने धर्म, दर्शन, भाषा, कला एवं संस्कृति की दृष्टि से एक पृथक समाज है जिसने अरसे बाद साहित्य मनीषियों का ध्यान आकर्षित किया। आदिवासी अपेक्षित रूप से सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। आदिवासी समाज के प्रति हमारे तथाकथित सभ्य, सुसंस्कृत समाज का नजरिया कितना स्वस्थ है? यह सोचने का विषय है। आमतौर पर आधुनिक शिक्षित समाज विशिष्टजन, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, आमजन सभी के मस्तिष्क में आदिवासियों को लेकर पहले-पहल यह विचार कौंधता है कि यह समाज (आदिवासी) कैसा है? इसकी दिनचर्या क्या है? भोजन, आवास, रहन-सहन, रीति-नीति और परंपरा क्या है? यदि देखा जाए तो आज की नई पीढ़ी के लिए यह समाज एक सस्ते मनोरंजन का साधन भर है। हम कहें कि तकनीकी सूचना और संचार क्रांति के युग में मीडिया द्वारा आज भी उन्हें आदमी की अलग प्रजाति के रूप में अजूबे की तरह पेश किया जाता है। वर्तमान युग में मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्र के अध्येताओं ने विलुप्त होती जनजातियों, कबीलों, जंगली समुदायों और समाजों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई हैं जो कोश ग्रंथों के रूप में उपलब्ध हैं। मानव मनोवैज्ञानिकों में वैज्ञानिकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई यह समस्त जानकारियां जहां हमारा ज्ञानवर्धन करती हैं, वहीं एक अनभिज्ञ, अपरिचित, आभासी दुनिया से रू-ब-रू कराती हैं। प्रत्येक समाज का अतीत बड़ा गहरा और महत्वपूर्ण होता है। आदिवासियों के संदर्भ में

भी यह सौ प्रतिशत सही है, किंतु सवाल यह उठता है कि क्या किसी भी समाज को जीने के लिए उसकी पारंपरिक पुरातन अवस्था में ही छोड़ दिया जाए अथवा उसे नए परिवेश में पनपने, समझने का अवसर प्रदान किया जाए। भूमंडलीकरण के दौर में जब समूचा विश्व एक गाँव में तब्दील हो रहा है, दूरियां मिट रही हैं, तब जल, जंगल और जमीन से गहरा जुड़ाव रखने वाले आदिवासियों के जीवन में भी आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। देश की व्यापक खनिज संपदा जल, जंगल, जमीन और दुर्गम पहाड़ी इलाके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं तब क्या यह जरूरी है कि देश की सीमित आबादी आदिवासियों को जीवनोपयोगी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर उनके अस्तित्व को ही मिटा दिया जाए। विगत कुछ वर्षों में निजीकरण के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। सरकारी संरक्षण प्राप्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों, निगम, उदारीकरण, औद्योगिककरण, शहरीकरण के नाम पर जनजातीय समूहों के मानवीय अधिकारों पर नुकीला प्रहार कर रहे हैं, उन्हें उनकी प्राकृतिक जीवनशैली, समाज-संरचना, सांस्कृतिक मूल्यों से बेदखल किया जा रहा है। आदिवासियों के आख्यान, उनके मिथक, परंपराएं, आस्था और विश्वासों को मिटाने का षडयंत्र रचा जा रहा है, लेकिन ये सब वर्तमान युग में भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वह भारत के समृद्ध अतीत के साथ-साथ पूरे विश्व के अतीत की गाथा दोहराते हैं। आखिर समूचे विश्व का इतिहास आदिवासियत का ही तो इतिहास है। आदिवासियों की कलात्मक अभिव्यक्ति, सौंदर्यात्मक और अनुष्ठानिक क्रियाएं साधारण चीज नहीं हैं बल्कि उनकी जिंदगी के पूरे फलसफे को समेटे हैं। अतः उनकी भाषा, जीवन शैली, संस्कृति और परम्परा का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है।